

VII. समष्टि आर्थिक परिदृश्य

राजकोषीय नीतिगत सुधारों के प्रति स्पष्ट रुख एवं अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए बहुप्रतीक्षित सक्रिय नीति के प्रति प्रतिबद्धता के बाद निवेश के निरूत्साहित वातावरण में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। इससे कारोबारी उत्साह को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो वैश्विक तथा घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की अनिश्चितताओं के चलते अनिश्चय की स्थिति में था। बाहरी एजेंसियों तथा पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने भारत की वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को संशोधित करके कम किया है। यदि घोषित घरेलू सुधार उपायों का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से किया जाता है और इनमें आगे और सुधार किये जाते हैं तो वर्तमान स्थितियों तथा कमजोर वैश्विक वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव आ सकता है। इस बीच नीतियों में बारीकी से समायोजन की जरूरत है ताकि समष्टि आर्थिक जोखिम को रोका जा सके।

सरकार की हाल की कार्रवाई से समष्टि आर्थिक जोखिम में कमी, परंतु इनका कार्यान्वयन जरूरी

VII.1 पिछले दो तिमाहियों के दौरान घरेलू वृद्धि की दर 5.4 प्रतिशत रही। यह दर 2011-12 के 6.6 प्रतिशत तथा 2008-09 के संकट प्रभावित दौर के 6.7 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। बचत और निवेश की गिरती दरों, बढ़ते दोहरे घाटे तथा बढ़ती मुद्रास्फीति सहित कमजोर आर्थिक संकेतकों को मिलाकर देखें तो एक वर्ष से कुछ अधिक की अवधि में संभावित वृद्धि दर में भी एक प्रतिशत अंक की गिरावट आई।

VII.2 ऋण तथा वित्तीय संकट के चलते सभी क्षेत्रों की वृद्धि दर तथा व्यापार में गिरावट आई और यही बात कमजोर वैश्विक वृद्धि का आंशिक कारण थी। परंतु, भारत में घरेलू कारकों ने वृद्धि दर में गिरावट की गति को और तेज किया। मुद्रास्फीति लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रही जिसके चलते मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, जिसके चलते अंशतः मुद्रास्फीति बढ़ी, को रोकने के लिए मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई करनी पड़ी। समष्टि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और मध्यावधि में वृद्धि दर को और आगे ले जाने के लिए मौद्रिक कड़ाई की जरूरत पड़ी। परंतु, इसके बाद नीति तथा कार्रवाई के मोर्चे पर पर्याप्त उपाय न किए जाने से निवेश के वातावरण, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय गिरावट के चलते पहले ही प्रभावित हो चुका था, पर प्रतिकूल असर पड़ा।

VII.3 सितंबर 2012 के मध्य से सरकार द्वारा घोषित कई नीतिगत उपायों के चलते इन चिंताओं का समाधान होना शुरू हुआ (सारणी

VII.1)। ये सुधारात्मक उपाय अपने आप में वृद्धि को बाधित करने वाली समष्टि तथा ढांचागत समस्याओं के समाधान और दोहरे घाटे में कमी लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी ये दिशात्मक बदलाव को दर्शाते हैं। टिकाऊ बहाली की शुरुआत करने के लिए प्रस्तावित उपायों का शीघ्रता से कार्यान्वयन एवं दोहरे घाटे को रोकने की दिशा में और प्रगति किए जाने की जरूरत है।

आर्थिक गिरावट पर अंकुश लग रहा है

VII.4 ये सुधार समष्टि वित्तीय जोखिम को कम करके घटती वृद्धि दर को लगाम लगा सकते हैं। यद्यपि 2012-13 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में उल्लेखनीय बदलाव की संभावना नहीं है, फिर भी वर्ष के आगे की अवधि में बहाली की शुरुआत हो सकती है।

VII.5 2012-13 में कई कारणों से वृद्धि दर में गिरावट आई। मानसून में वर्षा की कमी के चलते खरीफ फसलें प्रभावित हुईं। अगस्त और सितंबर में हुई अच्छी वर्षा के चलते मिट्टी की नमी तथा जलाशयों के जलस्तर में सुधार आया जिससे रबी की अच्छी फसल की संभावना बढ़ी है। परंतु कृषि के चलते समग्र वृद्धि दर में गिरावट आ सकती है क्योंकि खरीफ फसल की कमी की भरपाई पूरी तरह नहीं हो पाएगी।

VII.6 अवैध खनन की गतिविधियों पर की गई कार्रवाई के चलते खनन क्षेत्र में गिरावट जारी है। घरेलू निवेश एवं निजी अंतिम उपभोग व्यय के साथ-साथ बाह्य मांग में गिरावट की वजह से विनिर्मित उत्पादन का स्तर स्थिर हो गया है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर की गति भी व्यापार, परिवहन, होटल तथा संचार संबंधी कार्यकलापों का शेष अर्थव्यवस्था से संबंध होने के कारण धीमी रही है।

VII.7 निवेश के वातावरण में सुधार के साथ मामूली बहाली की संभावना के बावजूद 2012-13 में वृद्धि दर पूर्वानुमान से कम रहेगी।

मुद्रास्फीति का जोखिम बना हुआ है, इसके लिए नीतिगत उपायों में बारीकी से समायोजन की जरूरत है

VII.8 वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीति सहज स्तर से काफी ऊपर है। यह स्थिति पूर्व में दबाकर रखी गई मुद्रास्फीति के असर को दर्शाती है जो वर्तमान के मुद्रास्फीति के आंकड़ों में दिख रहा

सारणी VII.1: सितंबर 2012 के मध्य से किए गए प्रमुख सुधार उपाय

घोषणा की तारीख	सुधार के उपाय तथा प्रमुख विशेषताएं	प्रत्याशित परिणाम	क्या अनुमोदन लंबित है
1	2	3	4
सितं. 13, 2012	ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी: <ul style="list-style-type: none"> डीजल की कीमतों में 5 ₹/लीटर की बढ़ोतरी सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की अधिकतम प्रति वर्ष सीमा - 6/ प्रति परिवार 	2012-13 में डीजल की बिक्री पर कम वसूली की राशि में ₹150 बिलियन की कमी आएगी जिसका राजकोषीय समेकन में थोड़ा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रणाली की दमित मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी जिससे अल्पावधि में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होने पर भी मध्यावधि में इसका लाभ मिलेगा।	नहीं
सितं. 14, 2012	एफडीआई का उदारीकरण <ul style="list-style-type: none"> मल्टी ब्रांड एवं सिंगल ब्रांड खुदरा में एफडीआई 51% तक, शर्तों के अधीन टेलीफोनों, मोबाइल टीवी और स्काई ब्राडकास्टिंग सेवाओं में एफडीआई 74% तक विदेशी एयरलाइनों द्वारा एविशयन में एफडीआई 49 % तक 	अगले एक से तीन वर्षों में रीटेल में एफडीआई अंतर्वाह का स्तर मध्यम रहने की संभावना। इससे व्यवस्थित खुदरा कारोबार का विस्तार होगा परंतु इसका बाजार हिस्सा 10% से कम रह सकता है। समय के साथ सप्लाइ चैन के प्रबंधन में सुधार होने की संभावना जिससे कीमतों में कमी आने के साथ-साथ ग्राहकों के कल्याण में भी बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई को भी लाभ मिलेगा। निर्यात और आयात दोनों बढ़ सकते हैं। विमानन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पुनर्गठन एवं विलय और अधिग्रहण पर निर्भर करेगा। ब्राडकास्टिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से केबल तथा डाइरेक्ट-टू-होम खंड के जरिए समय के साथ डिजिटलीकरण में सुधार हो सकता है।	नहीं
सितं. 14, 2012	पीएसयू में विनिवेश आइल इंडिया लिमिटेड (10%), एमएमटीसी (9.33%), नालको (12.15%) और हिंदुस्तान कॉपर (9.59%)	केंद्रीय बजट 2012-13 में विनिवेश के लिए निर्धारित 300 बिलियन रुपये में से 150 बिलियन रुपये की राशि उगाही गई। साथ ही, दक्षता तथा बाजार अनुशासन में सुधार होगा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में शेयरहोल्डरों की जवाबदेही तथा कंपनी अभिशासन में बेहतर परिणाम आएंगे।	नहीं
सितं. 21, 2012	विद्वहोल्डिंग कर में कमी जुलाई 2012 से जून 2015 के दौरान घरेलू कंपनियों द्वारा विदेश से लिए गए उधार पर कर की दर 20% से घटकर 5%, शर्तों के अधीन	विदेश में कंपनी उधार की कम लागत। इससे पूंजी खाते में ऋण का प्रवाह बढ़ सकता है।	नहीं
सितं. 24, 2012	राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन	2010-11 के अंत में वितरण कंपनियों की संचित हानि की राशि 1.9 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान। पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन में कई दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु बिजली क्षेत्र की वित्तीय समस्या को कम करने की दिशा में यह एक उल्लेखनीय कदम होगा।	नहीं
सितं. 29, 2012	एक सीमा से ऊपर की ढांचागत परियोजनाओं को पारित करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के गठन का प्रस्ताव	ढांचागत निवेशों की अनुमति की प्रक्रिया शीघ्र होने से अधिक स्पष्टता आएगी एवं अनिश्चितता में कमी आएगी। इससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली देरी से बचा जा सकता है।	कैबिनेट का अनुमोदन लंबित
अक्तू. 1, 2012	बीमा क्षेत्र के लिए पैकेज	बीमा क्षेत्र में पूंजी बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा घरेलू बचतों को बढ़ावा मिलेगा।	आईआरडीए, सीबीडीटी तथा सीबीसी की अधिसूचनाएं लंबित
अक्तू. 4, 2012	एफडीआई में और उदारीकरण (बीमा और पेंशन में) पेंशन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 26% अथवा ऐसा प्रतिशत जिसे बीमा क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया जाए, इनमें से जो भी अधिक हो	भारत की दीर्घावधि वृद्धि में सुधार हेतु वैश्विक बचत की बड़ी मात्रा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। ऐसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अधिक स्थायी प्रकार की पूंजी मिलेगी तथा विनिमय दर में अधिक स्थिरता आएगी।	संसद का अनुमोदन जरूरी
अक्तू. 4, 2012	बारहवीं पंच-वर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित	बड़े स्तर के ढांचागत निवेश की योजनाएं बनने से अगले पांच वर्षों की वृद्धि की रूपरेखा तय हो पाएगी।	एनडीसी का अनुमोदन लंबित
अक्तू. 5, 2012	आर्थिक विधानों को पारित करना: कंपनी बिल 2011 में संशोधन के लिए सीसीईए का अनुमोदन, फरवार्ड कांटेक्ट (विनियमन) संशोधन बिल, 2010 और कंपनी अधिनियम 2002	बेहतर विधिक ढांचे से विविध लाभ मिलेगा।	संसद का अनुमोदन जरूरी

है क्योंकि नियंत्रित कीमतों का समायोजन उनमें बढ़ोतरी करके किया जाता है। इसने घटती वृद्धि दर के संबंध में मूल मुद्रास्फीति को ऊंचे स्तर पर बनाए रखा क्योंकि लागत-प्रेरित दबावों का असर कीमतों

में दिखता है। इसके अतिरिक्त, मांग पक्षीय दबावों का कुछ शेष हुआ हिस्सा अभी भी बना हुआ है क्योंकि हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति का दबाव काफी रहा है।

VII.9 कच्चे तेल की कीमतों में हाल में आई गिरावट के बावजूद, मात्रात्मक सहूलियत का चलनिधि से जुड़ा असर एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं पण्य कीमतों को बढ़ाने वाले जोखिम के रूप में उभरी हैं। घरेलू मोर्चे पर, सुधार उपायों के चलते नियंत्रित कीमतों में की गई बढ़ोतरी से अल्पावधि में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, परंतु मध्यावधि में राजकोषीय दबाव के कम होने से मुद्रास्फीति को कम करने में इससे मदद मिलेगी। आपूर्ति पक्षीय सीमाओं तथा कम प्रतिस्पर्धी बाजार ढांचे के चलते कीमतों पर दबाव बना रहेगा। कुछ पण्यों की निविष्टि लागत संबंधी दबाव काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप मजदूरी-कीमत के चक्र के चलते, उत्पादन अंतर के बने रहने के बावजूद, मुद्रास्फीति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है जिसके चलते मध्यावधि की मुद्रास्फीति के लिए काफी जोखिम उत्पन्न हो गया है। अल्पावधि में मुद्रास्फीति अनुमान से मामूली अधिक रहने की संभावना है। तथापि 2012-13 की चौथी तिमाही से इसके कम होने की संभावना है।

कारोबारी उत्साह कमजोर है, परंतु हाल की नीतिगत कार्रवाइयों से विश्वास को बल मिल सकता है

VII.10 विभिन्न कारोबारी विश्वास सर्वेक्षण में 2012-13 की पहली तथा दूसरी तिमाही में कारोबारी संभावना के संबंध में कमजोर उत्साह परिलक्षित होता है। एनसीएईआर के कारोबारी विश्वास सूचकांक समग्र विश्वास के मामले में 2012-13 की पहली तिमाही की तुलना में गिरावट दर्शाता है, परंतु एक वर्ष पूर्व की तुलना में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार फिक्की के कारोबार विश्वास सर्वेक्षण 2012-13 की पहली तिमाही में समग्र कारोबारी विश्वास में गिरावट दर्शाता है। फिक्की के सर्वेक्षण में कमजोर मांग, कर्ज की ऊंची कीमतें तथा रोजगार संभावनाओं की खराब होती स्थितियां बाधाओं के रूप में उभरी हैं। 2012-13 की दूसरी तिमाही में सीआईआई कारोबारी विश्वास सूचकांक में गिरावट आई जो कारोबारी विश्वास के कम स्तर पर रहने को दर्शाता है। सुधार की गति में ठहराव एवं ऋण की उपलब्धता संबंधी बाधाएं भी महत्वपूर्ण कारण रहीं (सारणी VII.2)।

VII.11 इन सर्वेक्षणों के अधिकांश उत्तर सुधार उपायों की घोषणा से पहले प्राप्त हो गए थे। जो उत्तर बाद में प्राप्त हुए उनमें बेहतर कारोबारी उत्साह के संकेत हैं। डुन एंड ब्रैडस्ट्रीट के 2012-13 की तीसरी तिमाही के कारोबारी उत्साह सूचकांक पिछली तिमाही की तुलना में स्थिति में सुधार दर्शाता है जो बेहतर उत्साह का द्योतक है।

VII.12 एचएसबीसी मार्केट पर्चेजिंग मैनेजर्स का मौसम समायोजित विनिर्मित वस्तुओं का सूचकांक सितंबर 2012 के दौरान पूर्ववत् रहा

सारणी VII.2: कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण

अवधि / सूचकांक	एनसीएईआर कारोबार विश्वास सूचकांक अक्टूबर 2012	फिक्की समग्र कारोबार विश्वास सूचकांक ति.1: 2012-13	डुन एंड ब्रैडस्ट्रीट कारोबार विश्वास सूचकांक ति.4: 2012	सीआईआई कारोबार विश्वास सूचकांक ति.2: 2012-13
1	2	3	4	5
सूचकांक का वर्तमान स्तर	125.4	51.8	140.8	51.3
पिछले सर्वेक्षण के अनुसार सूचकांक	126.6	60.3	136.1	55.0
एक वर्ष पूर्व सूचकांक का स्तर	125.4	51.6	143.7	53.6
क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन (तिमाही- दर-तिमाही)	-0.9	-14.1	3.5	-6.7
प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)	0.0	0.4	-2.0	-4.3

जबकि सेवाओं से संबंधित सूचकांक ने कारोबारी गतिविधियों में पिछले सात महीनों में सबसे तेज वृद्धि दर्शाई। परंतु, दोनों ही क्षेत्रों में निविष्टि की कीमतों में वृद्धि जारी रही जबकि सेवाओं के क्षेत्र में कारोबारी प्रत्याशा छह महीने के निचले स्तर तक गिर गई।

परंतु बेहतर परिदृश्य की ओर बदलाव दिखता है, हालांकि इसका स्तर कम है

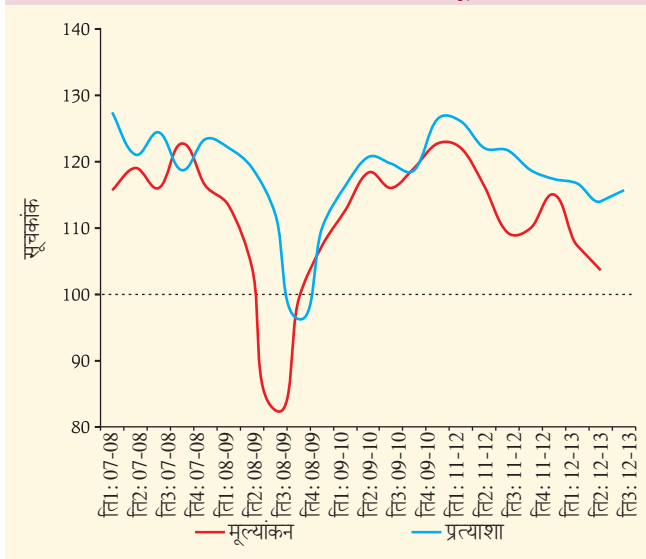
VII.13 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2012-13 की दूसरी तिमाही में किए गए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (<http://www.rbi.org.in/IOS59>) के 59वें दौर में तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के कारोबारी उत्साह में और गिरावट आने के संकेत हैं।

VII.14 कारोबारी प्रत्याशा सूचकांक (बीईआई), जो कई कारोबारी मानदंडों का संयुक्त संकेतक है, उस स्तर तक गिर गया जो संकट की शुरुआत के समय 2008-09 की तीसरी तिमाही में था। परंतु, सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि 2012-13 की आगामी तीसरी तिमाही की संभावना में मामूली सुधार हुआ है (चार्ट VII.1)।

VII.15 मांग की स्थिति, जैसा कि उत्पादन, आदेश बहियों, क्षमता के उपयोग, निर्यात तथा आयात से संबंधित निवल उत्तरों से स्पष्ट होता है, में तीसरी तिमाही में गिरावट के संकेत मिलते हैं। परंतु तीसरी तिमाही की संभावना में, निर्यातों तथा आयातों को छोड़कर, मामूली सुधार दिखाई दिया (सारणी VII.3)।

VII.16 इन सर्वेक्षणों के परिणाम भी 2012-13 की दूसरी तिमाही में समग्र वित्तीय स्थिति के बिगड़ने का संकेत देते हैं, परंतु तीसरी तिमाही की संभावना में मामूली सुधार दिखाई देता है। बाह्य वित्त की लागत में वृद्धि होने की संभावना है, हालांकि ऐसा कहने वाले लोगों का प्रतिशत कम था। कच्चे माल की लागत भी अगली तिमाही में कम दर पर बढ़ने की संभावना है। लाभ मार्जिन, जो पिछली कुछ तिमाहियों से

चार्ट VII.1: कारोबार प्रत्याशा सूचकांक



घट रहा था, के 2012-13 की तीसरी तिमाही में उसी स्तर पर बने रहने की संभावना है।

उपभोक्ताओं के विश्वास की बहाली होना शेष है

VII.17 सितंबर 2012 में किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (<http://www.rbi.org.in/CCS10>), का

10वां दौर चौथी तिमाही में भी सूचकांक में लगातार गिरावट दर्शाता है, हालांकि अद्यतन तिमाही में गिरावट मामूली थी।

VII.18 आर्थिक स्थितियों की वर्तमान धारणा, पारिवारिक स्थिति, आय, व्यय तथा मूल्य स्तरों पर आधारित वर्तमान स्थिति सूचकांक 106.2 आंका गया जबकि पिछली तिमाही का सूचकांक 106.7 था। परंतु आर्थिक स्थितियों की प्रत्याशा, आय, व्यय, मूल्य स्तर तथा रोजगार की संभावना आधारित भावी प्रत्याशा सूचकांक में इस तिमाही में काफी गिरावट आई (चार्ट VII.2)।

बाह्य एजेंसियों ने भारत की वृद्धि के पूर्वानुमानों में कमी की

VII.19 जीडीपी में वृद्धि के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए अद्यतन पूर्वानुमान 5.6 से 6.7 प्रतिशत के दायरे में हैं (सारणी VII.4)। इन पूर्वानुमानों के आंकड़ों को संशोधित करके पहले के अनुमानों के मुकाबले काफी कम किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.6 प्रतिशत किया है। उसने इसका कारण सुधारों में देरी के चलते निवेश तथा खपत में गिरावट, विशेष रूप से स्थावर संपदा तथा ढांचागत क्षेत्र में, बताया है।

सारणी VII.3: रिजर्व बैंक का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

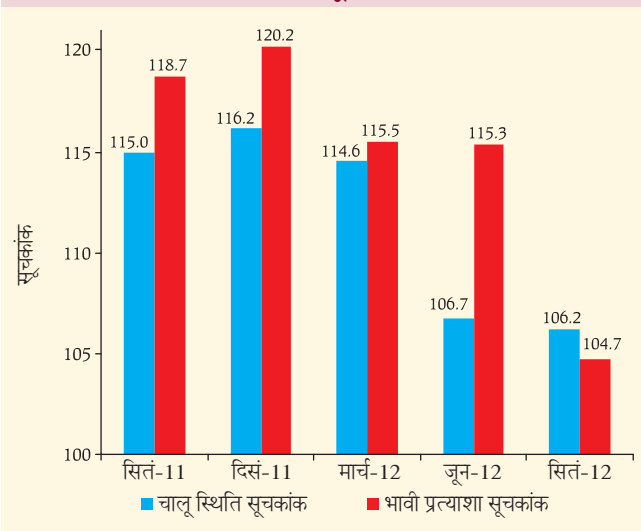
मानदंड	आशावादी उत्तर	निवल उत्तर								
		2011-12				2012-13				
		अक्तू-दिसं		जन-मार्च		अप्रै-जून		जुला-सितं		अक्तू-दिसं
		E	A	E	A	E	A	E	A	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कारोबार की समग्र स्थिति	बेहतर	35.2	17.7	33.6	26.5	34.9	18.3	30.6	16.1	32.2
2. समग्र वित्तीय स्थिति	बेहतर	26.3	11.2	25.2	18.5	27.7	14.2	23.6	12.2	25.8
3. उत्पादन	वृद्धि	39.9	25.3	40.4	33.1	34.7	20.3	33.6	18.8	35.7
4. आर्डर बुक	वृद्धि	33.4	18.4	31.3	24.8	29.5	16.9	29.9	12.0	30.3
5. क्षमता के उपयोग का स्तर	वृद्धि	22.2	10.8	24.3	16.7	19.9	8.6	18.4	6.3	20.0
6. निर्यात	वृद्धि	22.1	11.5	18.6	14.2	20.7	10.8	20.5	10.0	18.0
7. आयात	वृद्धि	16.9	11.6	15.5	14.4	15.7	11.6	15.5	9.8	14.0
8. कंपनी में रोजगार	वृद्धि	16.5	11.3	13.6	12.9	14.6	10.0	12.3	8.3	13.3
9. वित्त की उपलब्धता	सुधार	20.2	10.4	19.0	15.8	22.9	15.0	20.4	13.8	21.3
10. बाह्य वित्त की लागत	गिरावट	-41.0	-50.6	-38.8	-37.4	-22.7	-30.5	-24.0	-27.4	-20.6
11. कच्चे माल की लागत	गिरावट	-49.7	-61.2	-50.1	-59.4	-49.0	-63.1	-51.4	-59.6	-48.6
12. बिक्री मूल्य	वृद्धि	16.0	8.9	14.7	13.5	19.0	17.5	18.8	18.5	17.3
13. लाभ मार्जिन	वृद्धि	-1.6	-17.3	-2.9	-11.3	-1.2	-17.9	-3.6	-15.1	-1.3

‘निवल उत्तर’ की गणना ‘आशावादी’ (सकारात्मक) और ‘निराशावादी’ (नकारात्मक) धारणा की सूचना देने वाली कंपनियों के प्रतिशत हिस्से के अंतर के अनुसार की गयी है; यथापूर्व स्थिति (कोई परिवर्तन नहीं) के रूप में दी गयी सूचना को हिसाब में नहीं लिया गया है। उच्चतर ‘निवल उत्तर’ विश्वास के उच्चतर स्तर को और निम्नतर निवल उत्तर इसकी विपरीत स्थिति को दर्शाता है।

प्र: प्रत्याशा तिमाही के लिए उत्तर और

मू.: मूल्यांकन तिमाही के लिए उत्तर

चार्ट VII.2: चालू स्थिति सूचकांक और भावी प्रत्याशा सूचकांक



VII.20 आईएमएफ ने भी अक्टूबर 2012 में भारत की वृद्धि दर संबंधी पूर्वानुमान को कम करके 5.6 प्रतिशत कर दिया है। अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसने भारत की वृद्धि दर में कमी आने के कारणों में नई परियोजनाओं के देरी से अनुमोदन से कमजोर हुए कारोबारी विश्वास, ढांचागत सुधारों में देरी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीति दरों में बढ़ोतरी तथा गिरती बाह्य मांग को गिनाया है। उसने यह बात भी जोड़ी है कि उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए भारत को मौद्रिक नीति में नरमी लाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक और अधिक राजकोषीय समायोजन के साथ घरेलू मांग में कमी नहीं आ जाती।

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का पूर्वानुमान¹

VII.21 वृद्धि दर में आई गिरावट की पुष्टि रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण (<http://www.rbi.org.in/SPF21>) के 21वें दौर के परिणामों से भी होती है। 2012-13 के माध्य वृद्धि अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से कम करके 5.7 प्रतिशत किया गया है। समग्र रूप में 2012-13 की चौथी तिमाही से जीडीपी की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के संभावना है। यद्यपि 2012-13 की चौथी तिमाही से थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आने की संभावना है, फिर भी 2012-13 की दूसरी तिमाही तक इसके 7 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है। माध्य पूर्वानुमानकर्ताओं ने चालू खाता घाटे में गिरावट का संकेत दिया है, परंतु 2012-13 में राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्यों और सफलता में काफी अंतर रहने की संभावना व्यक्त की गई है (सारणी VII.5)।

¹ यह पूर्वानुमान पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के विचारों को दर्शाता है न कि रिजर्व बैंक के।

सारणी VII.4: 2012-13 के लिए एजेंसियों के अनुमान

एजेंसी	अद्यतन अनुमान		पूर्ववर्ती अनुमान	
	जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)	माह	जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)	माह
1	2	3	4	5
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	6.7	अग-12	7.6	Feb-12
वित्त मंत्रालय	7.6 (+/-0.25)	मार्च-12	-	-
एशियाई विकास बैंक	5.6	अक्टू-12	6.5	Jul-12
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष *	5.6	अक्टू-12	6.4	Jul-12
एनसीआईआर	6.4	जुला-12	7.3	Apr-12
ओईसीडी (बाजार मूल्य पर)	7.3	मई-12	7.5	Nov-11
विश्व बैंक	6.0	अक्टू-12	6.9	Jun-12

*: कैलेंडर वर्ष 2012 के लिए बाजार मूल्य पर जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अद्यतन पूर्वानुमान के अनुरूप है जिसे जुलाई 2012 में 6.1 प्रतिशत से कम किया गया।

घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा में गिरावट

VII.22 घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (<http://www.rbi.org.in/IESH29>) के अद्यतन दौर से संकेत मिलता है कि वर्तमान तिमाही (अर्थात् जुलाई-सितंबर 2012) में मुद्रास्फीति की धारणा तथा भविष्य की मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में गिरावट (तिमाही-दर-तिमाही) आई है। उन उत्तरदाताओं के प्रतिशत में गिरावट आई है जो यह आशा करते हैं कि अगली तिमाही में मूल्य में वृद्धि 'वर्तमान दर से अधिक दर' होगी। परंतु, अगले वर्ष की प्रत्याशा के मामले में पिछले दौर के सर्वेक्षण की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि हुई है। यह सर्वेक्षण डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से पहले किया गया था।

अर्थव्यवस्था को वृद्धि के पथ पर आगे ले जाने के लिए विश्वसनीय नीतिगत समन्वय महत्त्वपूर्ण

VII.23 सितंबर 2012 से सरकार द्वारा की गई नीतिगत कार्रवाई की घोषणा को गिरती वृद्धि दर की दिशा को पलटने की ओर एक महत्त्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। चूंकि ये उपाय प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित तथा आगे बढ़ाए जाते हैं अतः इन उपायों से भारत की वास्तविक और संभावित वृद्धि को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बहाली की स्थिति शीघ्रता से या विलंब से आएगी वह कई कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें वैश्विक स्थितियां भी शामिल हैं जो यूएस में श्रम तथा आवास बाजारों से कुछ अच्छी खबरों के बावजूद इस समय कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। परंतु, बहाली के लिए सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बीच नीतिगत समन्वय तथा ढांचागत परियोजना क्षेत्रों के बुनियादी अड़चनों को दूर करना जरूरी है।

**सारणी VII.5: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का चुनिंदा समष्टि आर्थिक संकेतकों का माध्यिका पुर्वानुमान -
2012-13 और 2013-14**

	वास्तविक 2011- 12	वार्षिक पूर्वानुमान				तिमाही पुर्वानुमान									
		2012-13		2013-14		2012-13					2013-14				
						ति2		ति3		ति4		ति1		ति2	
		पि.	अ.	पि.	अ.	पि.	अ.	पि.	अ.	पि.	अ.	पि.	अ.	पि.	अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. कारक लागत पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.5#	6.5	5.7	7.0	6.6	6.3	5.5	6.6	5.6	7.0	6.2	7.1	6.4	-	6.7
क. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2.8#	3.0	1.4	3.0	3.0	3.0	1.2	2.7	-0.3	2.9	1.5	2.8	2.4	-	2.5
ख. उद्योग	2.6#	4.0	3.0	5.7	5.3	3.7	1.9	5.0	3.2	5.5	3.9	6.0	4.6	-	5.1
ग. सेवाएं	8.5#	8.0	7.8	8.6	8.0	7.8	7.5	8.1	8.0	8.4	8.2	8.4	8.0	-	7.9
2. सकल देशी बचत (चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	-	31.3	30.3	32.2	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति	8.9	7.3	7.7	6.8	6.7	7.6	7.6 ^a	7.4	8.0	7.2	7.7	6.5	7.0	-	7.0
4. विनिमय दर (भा.र./ 1 अम.डॉलर अवधि के अंत में)	51.2	53.0	52.0	51.0	50.8	55.0	52.7 ^a	54.5	52.5	53.0	51.5	52.5	51.5	-	51.3
5. 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिलाभ (अवधि के अंत में)	8.6	8.1	8.0	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. निर्यात (वृद्धि दर, प्रतिशत में) [@]	23.7*	12.0	0.0	17.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. आयात (वृद्धि दर, प्रतिशत में) [@]	31.1*	8.3	-0.9	14.3	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. व्यापार शेष (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-189.8*	-	-	-	-	-45.5	-46.6	-46.2	-46.5	-47.3	-47.6	-45.6	-45.2	-	-47.0
9. चालू खाता घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	4.2*	3.6	3.5	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	5.1 [^]	5.5	5.7	5.1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पि. : पिछले दौर का अनुमान अ. : अद्यतन दौर का अनुमान #: संशोधित अनुमान *: प्रारंभिक
- : उपलब्ध नहीं। &: वास्तविक @ : बीओपी आधार पर अमरीकी डॉलर ^ : बजट अनुमान

टिप्पणी: अद्यतन दौर का तात्पर्य सितंबर 2012 को समाप्त तिमाही से है जबकि पिछले दौर का तात्पर्य जून 2012 को समाप्त तिमाही के 20वें दौर से है।

स्रोत: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, दूसरी तिमाही 2012-13

VII.24 इस बात की भी जरूरत है कि दोहरे घाटे को कम करके समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार के उपाय किए जाएं। इसके लिए राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बने रहने की जरूरत है, साथ ही चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए व्यय में समायोजन के चुनिंदा उपायों के जरिए निजी उपभोग मांग को सबल बनाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि मुद्रास्फीति एक ऐसे स्तर पर बनी रहती है जिसके बाद उच्च वृद्धि को बनाए रखना तर्कसंगत नहीं होगा।

VII.25 हम आज जिस ढांचागत मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं उसके समाधान के लिए विनिमय दर एक पुख्ता औजार नहीं है। अंततोगत्वा राजकोषीय नीति को आपूर्ति-पक्षीय उपायों को तेज करने

तथा निजी खपत मांग को उचित नियंत्रण में रखने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

VII.26 अल्पावधि में मौद्रिक नीति का उपयोग वृद्धि दर को यथासंभव बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए काफी सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। उपभोक्ता के कल्याण तथा के समानता की दृष्टि से मुद्रास्फीति को कम करना जरूरी है, साथ ही मध्यावधि में वहनीय वृद्धि के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। यदि मुद्रास्फीति और दोहरे घाटे से समष्टि अर्थव्यवस्था पर होने वाले जोखिम में और कमी आती है तो आगे चलकर मौद्रिक नीति को वृद्धि संबंधी चिंताओं का समाधान करने का अवसर मिलेगा।